

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर पीठ

एस ब सिविल रिट याचिका संख्या 6008/2022

मुकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री जय प्रकाश शर्मा, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम नारादपुरा, डाकघर धनाऊ कलां, तहसील बस्सी, जिला जयपुर (राजस्थान) (सेवा समाप्ति के समय, याचिकाकर्ता पुलिस लाइन, टॉक में कांस्टेबल बेल्ट नंबर 992 के पद पर तैनात था)

-----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, प्रधान सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
- पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर।
- पुलिस महानिरीक्षक, अजमेर रेंज, जयपुर रोड, अजमेर।
- पुलिस अधीक्षक, टॉक, जिला टॉक (राजस्थान)।

-----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री दिनेश यादव

प्रतिवादी की ओर से : श्री प्रदीप कालवानिया, जी.सी.

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमान गणेश राम मीणा

आदेश

आरक्षित तिथि :::: 31 मई, 2024

घोषित तिथि :::: 01 जुलाई, 2024

रिपोर्ट करने योग्य

1. यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा जारी 08.04.2022 के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई है जिसके तहत उसे तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता, पुलिस अधीक्षक, जिला टोंक के अधीन एक कांस्टेबल के रूप में काम करते हुए, उसके खिलाफ जांच के विचार के मद्देनजर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 (संक्षेप में '1958 के नियम') के नियम 13(1)(a) के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24.10.2021 के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया था।

17.02.2022 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल कर दिया गया, जबकि उसके खिलाफ जांच की कार्यवाही लंबित रही।

3. याचिकाकर्ता के खिलाफ 01.12.2021 के आदेश द्वारा एक प्रारंभिक जांच का आदेश दिया गया था, जो उसके द्वारा आपत्तिजनक भाषा के उपयोग के आरोपों के मद्देनजर

सर्किल ऑफिसर, सर्किल मालपुरा को सौंप दिया गया था। प्रारंभिक जांच लंबित रहने के दौरान पुलिस अधीक्षक, जिला टोंक ने 08.04.2022 को एक आदेश जारी किया और सेवा से बर्खास्तगी की बड़ी शास्ति (penalty) लगाई। 08.04.2022 का आदेश पारित करते समय, 1958 के नियमों के नियम 19 (ii) के तहत दी गई विशेष शक्तियों का प्रयोग जांच की कार्यवाही को समाप्त करने के लिए किया गया था, जिसमें यह देखा गया कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण फाइल में दर्ज कारणों से संतुष्ट है कि उसके खिलाफ जांच के संबंध में नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना उचित रूप से संभव नहीं है।

4. रिट याचिका में किए गए मुख्य आरोप और याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित होने वाले वकील द्वारा मौखिक प्रस्तुति यह है कि प्रतिवादियों ने

याचिकाकर्ता के खिलाफ शास्ति का आदेश पारित करने से पहले जांच की कार्यवाही को समाप्त करने के लिए 1958 के नियमों के नियम 19 (ii) के तहत दी गई विशेष शक्तियों का अवैध और मनमाने ढंग से प्रयोग किया है। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने विभाग के उच्च अधिकारी के साथ सेल फोन पर बातचीत में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि क्या यह याचिकाकर्ता ही था जिसने उच्च अधिकारी के साथ सेल फोन पर बातचीत में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था या कोई और, यह केवल याचिकाकर्ता के वॉइस सैंपल को लेने और उसे परीक्षण के लिए फॉरेंसिक प्रयोगशाला में भेजने सहित एक उचित जांच करने के बाद ही पता लगाया जा सकता है। वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी 1958 के नियमों के तहत दी गई प्रक्रिया के तरीके से जांच की कार्यवाही के साथ आगे बढ़ सकते थे और 1958 के नियमों के नियम 19(ii) के तहत दी गई शक्तियां दुर्लभतम मामलों में प्रयोग की जाने वाली विशेष शक्तियां हैं जहां जांच की कार्यवाही संभव नहीं है, लेकिन प्रतिवादियों ने ऐसा करने के लिए किसी भी ठोस कारण के बिना शक्तियों का दुरुपयोग किया। वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का घोर उल्लंघन है। इसलिए, इसे रद्द किया जाना चाहिए।

5. प्रतिवादियों ने रिट याचिका का एक विस्तृत जवाब दायर किया है और प्रतिवादियों के लिए उपस्थित वकील ने मौखिक प्रस्तुतियों में कहा है कि आक्षेपित आदेश कानून के अनुसार पारित किया गया है। वकील ने

यह भी प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों ने उच्च अधिकारी के साथ सेल फोन पर बातचीत के दौरान उसके द्वारा आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करने के आरोपों के मद्देनजर याचिकाकर्ता के खिलाफ 1958 के नियमों के नियम 19(ii) के तहत दी गई विशेष शक्तियों का सही ढंग से प्रयोग किया है। वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि बातचीत में याचिकाकर्ता ने स्वयं अपनी पहचान का खुलासा किया है। राज्य के वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि 1958 के नियमों के नियम 19(ii) के तहत शक्तियों का उपयोग करने के कारणों को कार्यालय की फाइल पर लिखित रूप में दर्ज किया गया है। राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश उचित और सही है और इस न्यायालय के किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. संबंधित पक्षों के लिए उपस्थित दोनों वकीलों द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया गया।

7. मामले का मुख्य सार यह है कि क्या वर्तमान मामले में 1958 के नियमों के नियम 19(ii) के तहत शक्तियों का उपयोग करना उचित और सही है और क्या याचिकाकर्ता की सेवा से बर्खास्तगी का आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है?

8. प्रतिवादियों ने रिट याचिका के जवाब में एक प्रारंभिक आपत्ति भी उठाई है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका विचार योग्य नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता के पास 1958 के नियमों के तहत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील का वैधानिक वैकल्पिक उपाय है।

9. याचिका से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता पर आरोप है कि विभाग के उच्च अधिकारी के साथ बातचीत के दौरान उसने अशोभनीय

और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है और अपनी पहचान का भी खुलासा किया है, जिसे प्रतिवादियों द्वारा महिलाओं और अन्य व्यक्तियों के प्रति अशोभनीय व्यवहार माना जा रहा है।

उपरोक्त आरोपों पर प्रतिवादियों ने 01.12.2021 के आदेश द्वारा प्रारंभिक जांच का आदेश दिया था और उससे पहले 24.10.2021 के आदेश द्वारा जांच के विचार में याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया था। 17.02.2022 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल कर दिया गया, जबकि जांच की कार्यवाही लंबित रही।

याचिकाकर्ता ने जवाब के साथ पुलिस अधीक्षक, जिला टोंक द्वारा जारी 08.04.2022 का पत्र और उप पुलिस अधीक्षक, सर्किल मालपुरा जिला टोंक द्वारा जारी 25.08.2022 का पत्र भी रिकॉर्ड पर रखा है। 08.04.2022 के पत्र द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक ने उप पुलिस अधीक्षक, सर्किल, मालपुरा, जिला टोंक को याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों के संबंध में प्रारंभिक जांच को पूरा करने का निर्देश दिया था और उप पुलिस अधीक्षक, सर्किल मालपुरा, जिला टोंक ने 25.08.2022 के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता को 26.08.2022 को अपने समक्ष प्रारंभिक जांच में उपस्थित होने के लिए कहा था।

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जब पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का आक्षेपित आदेश जारी किया गया था, तब भी याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों के संबंध में प्रारंभिक जांच चल रही थी। आक्षेपित आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों के संबंध में नियमों के तहत दी गई प्रक्रिया के अनुसार जांच करना उचित रूप से संभव नहीं है।

10. कोई भी ठोस सामग्री के अभाव में यह न्यायालय यह राय बनाने में विफल रहता है कि यह एक ऐसा मामला है जहां याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में कार्यवाही को पूरा करने के लिए नियमों के तहत दी गई प्रक्रिया का पालन करना अनुचित और असंभव है। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप विभाग के उच्च अधिकारी के साथ बातचीत में अशोभनीय और आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करने का है और बातचीत के दौरान पहचान का भी याचिकाकर्ता द्वारा खुलासा किया गया था। अब क्या यह केवल याचिकाकर्ता ही था जिसने उच्च अधिकारी के साथ अशोभनीय और आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करते हुए बातचीत की थी या कोई और। यह भी संभव हो सकता है कि किसी और ने याचिकाकर्ता के नाम पर अपनी पहचान का दुर्भावनापूर्ण रूप से खुलासा करके ऐसी भाषा का उपयोग किया हो। क्या यह याचिकाकर्ता था या कोई और, इसका पता केवल फॉरेंसिक प्रयोगशाला द्वारा याचिकाकर्ता की आवाज के सत्यापन सहित एक पूर्ण जांच द्वारा ही लगाया जा सकता था, लेकिन प्रतिवादियों ने उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया बल्कि सेवा से बर्खास्तगी का आदेश पारित कर दिया, बिना किसी ऐसी सामग्री को बताए और प्रकट किए जिसके कारण अनुशासनात्मक प्राधिकारी को यह संतुष्टि हुई कि इस मामले में नियमों के तहत दी गई जांच की सामान्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा सकता है।

11. 1958 के नियमों के नियम 19(ii) को 1958 के नियमों में शामिल किया गया है, जो इस प्रकार उद्धृत है:

"19. कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया:

नियम 16, 17 और 18 में निहित किसी भी चीज के होते हुए भी;

(i) " "

(ii) जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए

जाने वाले कारणों से संतुष्ट है कि

उक्त नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना

उचित रूप से संभव नहीं है, या"

1958 के नियमों के नियम 19(ii) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के परंतुक (b) के प्रावधानों के मद्देनजर नियमों में शामिल किया गया है, जो इस प्रकार है:

"अनुच्छेद 311. संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों को पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पदावनत किया जाना।—

(1) " " "

(2) जैसा कि ऊपर कहा गया है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को तब तक पदच्युत या पद से हटाया या पदावनत नहीं किया जाएगा जब तक कि

एक जांच के बाद उसे उसके खिलाफ आरोपों के बारे में सूचित नहीं किया गया हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का एक उचित अवसर नहीं दिया गया हो:

बशर्ते कि जहां ऐसी जांच के बाद उस पर कोई ऐसी शास्ति लगाने का प्रस्ताव हो,

ऐसी शास्ति ऐसी जांच के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर लगाई जा सकती है और

ऐसे व्यक्ति को प्रस्तावित शास्ति पर कोई अभ्यावेदन करने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा:

बशर्ते आगे कि यह खंड लागू नहीं होगा:— (a) जहां किसी व्यक्ति को ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत या पद से हटाया या पदावनत किया जाता है जिसके कारण उसे किसी आपराधिक आरोप पर दोषी ठहराया गया है; या

(b) जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पदावनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी लिखित रूप में उस प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए जाने वाले किसी कारण से संतुष्ट है कि ऐसी जांच करना उचित रूप से संभव नहीं है; या

(c) जहां राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, इस बात से संतुष्ट है कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच करना समीचीन नहीं है।"

12. भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) और 1958 के नियमों के नियम 19(ii) की भाषा ऐसी स्थिति से निपटने के लिए है जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी संतुष्ट है कि उक्त नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना उचित रूप से संभव नहीं है।

अर्थात्, जब जांच करना असंभव या एक अर्थ में असंभव हो जाता है, तभी अनुशासनात्मक प्राधिकारी संबंधित सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शास्ति का आदेश पारित करने के लिए 1958 के नियमों के नियम 19(ii) के तहत दी गई शक्ति का प्रयोग कर सकता है। प्रतिवादियों ने जवाब के जवाब में किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया है जिसके कारण अनुशासनात्मक प्राधिकारी को यह संतुष्टि हुई कि

याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों के संबंध में जांच करना और पूरा करना उसके लिए अनुचित रूप से संभव क्यों है।

आरोपों और मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, प्रतिवादी याचिकाकर्ता से उसकी आवाज का नमूना देने के लिए कह सकते थे ताकि यह परीक्षण किया जा सके कि विभाग के उच्च अधिकारी के साथ आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करके की गई बातचीत केवल याचिकाकर्ता द्वारा ही की गई थी। याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका में यह प्रार्थना भी की है कि प्रतिवादियों को उसकी आवाज का नमूना लेने और उसे एफएसएल परीक्षण के लिए भेजने का निर्देश दिया जाए, जो यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता ने अपनी आवाज का नमूना देने से इनकार नहीं किया है और प्रतिवादी भी यह बताने के लिए सामने नहीं आए हैं कि याचिकाकर्ता ने आवाज के नमूने के लिए इनकार किया।

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्य बनाम तुलसिराम पटेल के मामले में, रिपोर्टेड इन (1985) 3 SCC 398 और अन्य संबंधित मामलों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के साथ पठित 1958 के नियमों के नियम 19(ii) के तहत दी गई अनुशासनात्मक प्राधिकारी की शक्तियों पर विस्तार से चर्चा की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तुलाराम पटेल (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय के प्रासंगिक पैरा नंबर 27, 29, 60, 101, 110, 116, 121, 130, 134, 140, 141 और 147 इस प्रकार हैं:-**

"27. अनुच्छेद 311, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, निम्नलिखित शर्तों में था:

"311. संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों को पदच्युत करना, हटाना या पद में अवनत करना।

(1) किसी व्यक्ति को, जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है अथवा संघ या किसी राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उसे उस प्राधिकारी द्वारा पदच्युत या हटाया नहीं जाएगा जो उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी से अधीनस्थ है।

(2) जैसा कि उपरोक्त कोई भी व्यक्ति, जब तक कि उसे उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में कारण बताने का एक उचित अवसर नहीं दिया गया है, तब तक उसे पदच्युत या हटाया नहीं जाएगा या पद में अवनत नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि यह खंड लागू नहीं होगा-

(क) जहां किसी व्यक्ति को ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत या हटाया या पद में अवनत किया जाता है, जिसके कारण उसे किसी आपराधिक आरोप पर दोषी ठहराया गया है;

(ख) जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या हटाने या उसे पद में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि किसी कारण से, जिसे उस प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाना है, उस व्यक्ति को कारण बताने का अवसर देना उचित रूप से संभव नहीं है; या

(ग) जहां राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख, जैसा भी मामला हो, इस बात से संतुष्ट है कि राज्य की सुरक्षा के हित में उस व्यक्ति को ऐसा अवसर देना उचित नहीं है।

(3) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या किसी व्यक्ति को खंड (2) के तहत कारण बताने का अवसर देना उचित रूप से संभव है, तो उस पर पदच्युत करने या हटाने या उसे पद में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का निर्णय, जैसा भी मामला हो, अंतिम होगा।

अनुच्छेद 311(2) के परंतुक के खंड (ग) में "या राजप्रमुख" शब्द को संविधान (सातवें संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा हटा दिया गया था।

29. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 ने 3 जनवरी, 1977 से अनुच्छेद 311 के प्रतिस्थापित खंड (2) में कुछ संशोधन किए। इस प्रकार संशोधित अनुच्छेद 311 इस प्रकार है:

"311. संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों को पदच्युत करना, हटाना या पद में अवनत करना।

(1) किसी व्यक्ति को, जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है अथवा संघ या किसी राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उसे उस प्राधिकारी द्वारा पदच्युत या हटाया नहीं जाएगा जो उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी से अधीनस्थ है।

(2) जैसा कि उपरोक्त कोई भी व्यक्ति, किसी जांच के बाद ही, जिसमें उसे उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दी गई है और उन आरोपों के संबंध में सुने जाने का एक उचित अवसर दिया गया है, तब ही उसे पदच्युत या हटाया या पद में अवनत किया जाएगा:

बशर्ते कि जहां ऐसी जांच के बाद उस पर कोई ऐसा दंड अधिरोपित करने का प्रस्ताव है, तो ऐसा दंड ऐसी जांच के दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर अधिरोपित किया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति को प्रस्तावित दंड पर अभ्यावेदन करने का कोई अवसर देना आवश्यक नहीं होगा:

इसके अलावा, बशर्ते कि यह खंड लागू नहीं होगा-

(क) जहां किसी व्यक्ति को ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत या हटाया या पद में अवनत किया जाता है, जिसके कारण उसे किसी आपराधिक आरोप पर दोषी ठहराया गया है; या

(ख) जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या हटाने या उसे पद में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि किसी कारण से, जिसे उस प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाना है, ऐसी जांच करना उचित रूप से संभव नहीं है; या

(ग) जहां राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, इस बात से संतुष्ट है कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच करना उचित नहीं है।

(3) यदि, जैसा कि उपरोक्त किसी व्यक्ति के संबंध में, यह प्रश्न उठता है कि क्या खंड (2) में संदर्भित ऐसी जांच करना उचित रूप से संभव है, तो उस पर उस व्यक्ति को पदच्युत करने या हटाने या उसे पद में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

ऊपर बताए गए मूल और संशोधित अनुच्छेद 311 से यह पता चलेगा कि मूल अनुच्छेद 311 का केवल खंड (1) अपरिवर्तित रहता है, जबकि अन्य दोनों खंड संवैधानिक संशोधनों का विषय बन गए हैं। किसी भी पक्ष द्वारा संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 द्वारा मूल के स्थान पर वर्तमान खंड (3) के प्रतिस्थापन पर कोई दलील नहीं दी गई, इसका स्पष्ट कारण यह है कि ऐसा प्रतिस्थापन केवल खंड (3) को खंड (2) के अनुरूप लाने के लिए किया गया था जैसा कि उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

60. अनुच्छेद 311 का खंड (2) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और ऑडी ऑल्टरम पार्टम नियम को एक संवैधानिक जनादेश देता है, जिसमें यह प्रावधान है कि संघ या किसी राज्य के तहत सिविल हैसियत में नियोजित किसी व्यक्ति को सेवा से तब तक पदच्युत या हटाया नहीं जाएगा या पद में अवनत नहीं किया जाएगा जब तक कि एक जांच के बाद उसे उसके विरुद्ध आरोपों के बारे में सूचित नहीं किया जाता है और उसे उन आरोपों

के संबंध में सुने जाने का एक उचित अवसर नहीं दिया जाता है। इस हद तक, अनुच्छेद 310(1) में अधिनियमित 'प्लेजर सिद्धांत' (*pleasure doctrine*) को कम कर दिया गया है क्योंकि अनुच्छेद 311(2) संविधान का एक स्पष्ट प्रावधान है। हालांकि, अनुच्छेद 311(2) द्वारा एक सरकारी कर्मचारी के लिए प्रदान की गई यह सुरक्षा तब समाप्त हो जाती है जब उस खंड का दूसरा परंतुक लागू होता है। हालांकि, अनुच्छेद 311(1) द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा बरकरार रहती है और सरकारी कर्मचारी के लिए उपलब्ध बनी रहती है। अनुच्छेद 311(2) का दूसरा परंतुक उस परंतुक के खंड (क) से (ग) में उल्लिखित तीन मामलों में लागू होता है। ये मामले हैं:

(क) जहां किसी व्यक्ति को ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत या हटाया या पद में अवनत किया जाता है, जिसके कारण उसे किसी आपराधिक आरोप पर दोषी ठहराया गया है; या

(ख) जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या हटाने या उसे पद में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि किसी कारण से, जिसे उस प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाना है, ऐसी जांच करना उचित रूप से संभव नहीं है; और

(ग) जहां राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, इस बात से संतुष्ट है कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच करना उचित नहीं है।

दूसरे परंतुक पर लगाए जाने वाले निर्माण और उस परंतुक के दायरे और प्रभाव पर बार (न्यायपालिका) में बहुत बहस हुई। हीरालाल रतनलाल आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, [1973] 2 S.C.R. 502 के मामले में इस न्यायालय ने देखा (पृष्ठ 512 पर);

"एक वैधानिक प्रावधान का निर्माण करने में, निर्माण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम साहित्यिक निर्माण है। हमें शुरू में ही यह देखना होगा

कि वह प्रावधान क्या कहता है? यदि प्रावधान *unambiguous* है और यदि उस प्रावधान से विधायी मंशा स्पष्ट है, तो हमें *statutes* के निर्माण के अन्य नियमों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। *statutes* के निर्माण के अन्य नियमों की सहायता तभी ली जाती है जब विधायिका की मंशा स्पष्ट न हो। सामान्यतः, एक धारा का परंतुक मुख्य धारा के एक हिस्से को विशेष उपचार के लिए बाहर निकालने के लिए होता है। इसे मुख्य धारा के दायरे को बढ़ाने की उम्मीद नहीं है। लेकिन ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें इस न्यायालय ने माना है कि इस तथ्य के बावजूद कि एक प्रावधान को परंतुक कहा जाता है, यह वास्तव में एक अलग प्रावधान है और तथाकथित परंतुक ने मुख्य धारा को काफी हद तक बदल दिया है।"

कमिश्नर ऑफ़ इनकम टैक्स, मद्रास बनाम मदुरै मिल्स कंपनी लिमिटेड, [1973] 3 S.C.R. 662 में, इस न्यायालय ने कहा (पृष्ठ 669 पर):

"एक परंतुक को किसी अधिनियम के दायरे को बढ़ाने के रूप में निर्मित नहीं किया जा सकता है जब इसे उस प्रभाव को बताए बिना निष्पक्ष और ठीक से निर्मित किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि *statutes* के अधिनियमित भाग की भाषा स्पष्ट और *unambiguous* है और इसमें वे प्रावधान नहीं हैं जो इसमें होने के लिए कहे जाते हैं, तो कोई भी उन प्रावधानों को एक परंतुक से निहितार्थ के रूप में प्राप्त नहीं कर सकता है।"

101. इसलिए, न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को संशोधित किया जा सकता है, बल्कि असाधारण मामलों में उन्हें बाहर भी रखा जा सकता है। नेमो जुडेक्स इन कौसा सुआ (*nemo judex in causa sua*) नियम के साथ-साथ ऑडी ऑल्टरम पार्टम (*audi alteram partem*) नियम के भी अच्छी तरह से परिभाषित अपवाद हैं। नेमो जुडेक्स इन कौसा सुआ नियम

आवश्यकता के सिद्धांत के अधीन है और जैसा कि इस न्यायालय द्वारा जे. मोहपात्रा एंड कंपनी और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य [1985] 1 S.C.R. 322,334-5 में बताया गया है, यह इसके अधीन है। जहां तक ऑडी ऑल्टरम पार्टम नियम का संबंध है, इंग्लैंड और भारत दोनों में, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जहां किसी आदेश को पारित करने से पहले पूर्व सूचना और सुनवाई का अवसर लेने का अधिकार त्वरित कार्रवाई करने में बाधा उत्पन्न करेगा, ऐसे अधिकार को बाहर रखा जा सकता है। इस अधिकार को वहां भी बाहर रखा जा सकता है जहां की जाने वाली कार्रवाई की प्रकृति, उसका उद्देश्य और प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों की योजना उसके बहिष्कार की वारंटी देती है; न ही ऑडी ऑल्टरम पार्टम नियम को लागू किया जा सकता है यदि इसे लागू करने से प्रशासनिक प्रक्रिया को *paralyzed* करने का प्रभाव पड़ेगा या जहां त्वरितता की आवश्यकता या कार्रवाई करने की तत्काल आवश्यकता इसकी मांग करती है, जैसा कि मेनका गांधी के मामले में पृष्ठ 681 पर बताया गया है। यदि कानून और किसी स्थिति की आवश्यकताएं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बाहर कर सकती हैं, जिसमें ऑडी ऑल्टरम पार्टम नियम भी शामिल है, तो एक प्रावधान या संविधान भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि एक संवैधानिक प्रावधान में एक वैधानिक प्रावधान की तुलना में कहीं अधिक और सर्वव्यापी पवित्रता होती है। वर्तमान मामले में, अनुच्छेद 311 का खंड (2) दूसरे परंतुक के शुरुआती शब्दों और विशेष रूप से इसके मुख्य शब्दों "यह खंड लागू नहीं होगा" द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अनुच्छेद 311 का खंड (2) स्पष्ट शब्दों में ऑडी ऑल्टरम पार्टम नियम को समाहित करता है। प्राकृतिक न्याय के इस सिद्धांत को एक संवैधानिक प्रावधान, अर्थात्, अनुच्छेद 311 के खंड (2) के दूसरे परंतुक

द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर रखे जाने के कारण, उसी जांच को फिर से प्रदान करने के लिए इसे एक साइड-डोर से फिर से पेश करने की कोई गुंजाइश नहीं है जिसे संवैधानिक प्रावधान ने स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया है। जहां दूसरे परंतुक के एक खंड को किसी बाहरी आधार पर या उस खंड में परिकल्पित स्थिति से कोई संबंध नहीं रखने वाले आधार पर लागू किया जाता है, तो इसे लागू करने में कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण होगी, और, इसलिए, शून्य होगी। ऐसे मामले में अमान्य करने वाला कारक अनुच्छेद 14 से संबंधित हो सकता है। हालांकि, यह एकमात्र दायरा है जो अनुच्छेद 14 का दूसरे परंतुक के संबंध में हो सकता है। लेकिन यह मानना कि एक बार जब दूसरा परंतुक ठीक से लागू हो जाता है और अनुच्छेद 311 का खंड (2) बाहर हो जाता है, तो अनुच्छेद 14 खंड (2) का स्थान लेने के लिए कदम उठाएगा, यह दूसरे परंतुक के शुरुआती शब्दों के प्रभाव को खत्म करने और इस प्रकार संविधान निर्माताओं की मंशा को विफल करने के लिए होगा। दूसरा परंतुक सार्वजनिक नीति पर आधारित है और सार्वजनिक हित में और सार्वजनिक भलाई के लिए है और संविधान - निर्माताओं ने जिन्होंने इसे अनुच्छेद 311(2) में डाला, वे यह तय करने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति थे कि ऐसा कोई बहिष्करण प्रावधान होना चाहिए और जिन स्थितियों में यह प्रावधान लागू होना चाहिए।

110. रेलवे सेवक नियमों का नियम 14 इस प्रकार प्रदान करता है:

"14. कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया। नियम 9 से 13 में निहित किसी भी बात के बावजूद:

(i) जहां किसी रेलवे सेवक पर ऐसे आचरण के आधार पर कोई दंड लगाया जाता है, जिसके कारण उसे किसी आपराधिक आरोप पर दोषी ठहराया गया है; या

(ii) जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना है, उन कारणों से संतुष्ट है कि इन नियमों में प्रदान किए गए तरीके से जांच करना उचित रूप से संभव नहीं है; या

(iii) जहां राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट है कि राज्य की सुरक्षा के हित में, इन नियमों में प्रदान किए गए तरीके से जांच करना उचित नहीं है;

अनुशासनात्मक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकता है और उस पर ऐसे आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे;

बशर्ते कि आयोग से परामर्श किया जाएगा, जहां ऐसे परामर्श आवश्यक हैं, इस नियम के तहत किसी भी मामले में कोई आदेश दिए जाने से पहले।"

रेलवे सेवक नियमों के नियम 2 के खंड (ख) में "आयोग" शब्द को "संघ लोक सेवा आयोग" के रूप में परिभाषित किया गया है।

116. अगला सेवा नियम जो इन मामलों में विचार के लिए आता है, वह सिविल सेवा नियमों का नियम 19 है। सिविल सेवा नियम भी अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित इन नियमों की योजना रेलवे सेवक नियमों के समान है। नियम 11 उन दंडों को निर्दिष्ट करता है जो एक सरकारी सेवक पर लगाए जा सकते हैं। इन दंडों को *minor penalties* और *major penalties* में विभाजित किया गया है। उस नियम के खंड (i) से (iv) यह निर्दिष्ट करते हैं कि *minor penalties* क्या हैं जबकि खंड (v) से (viii) यह निर्दिष्ट करते हैं कि *major penalties* क्या हैं। *major penalties* में अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से हटाया जाना शामिल है जो सरकार के तहत भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगी और सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतः सरकार के तहत भविष्य के रोजगार के लिए एक अयोग्यता होगी। नियम 14 और 15 उस प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं जिसका पालन किया जाना है जहां एक

major penalty लगाई जानी है जबकि नियम 16 एक *minor penalty* लगाने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। पहले, नियम 15 के उप-नियम (4) के तहत सरकारी सेवक को प्रस्तावित दंड के बारे में एक नोटिस भी दिया जाना था और ऐसे प्रस्तावित दंड के संबंध में अभ्यावेदन करने का एक अवसर भी दिया जाना था। हालांकि, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासन सुधार विभाग) अधिसूचना संख्या 11012/2/77 - *Ests.* दिनांक 18 अगस्त, 1978 द्वारा, उप-नियम (4) को संविधान (बयालीसवें संशोधन) अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 311 के खंड (2) में किए गए संशोधन के अनुरूप लाने के लिए एक नए उप-नियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, और प्रस्तावित दंड के खिलाफ कारण बताने का अवसर समाप्त कर दिया गया था। नियम 19 इस प्रकार प्रदान करता है "

19. कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया- नियम 14 से नियम 18 में निहित किसी भी बात के बावजूद-

(i) जहां किसी सरकारी सेवक पर ऐसे आचरण के आधार पर कोई दंड लगाया जाता है, जिसके कारण उसे किसी आपराधिक आरोप पर दोषी ठहराया गया है, या

(ii) जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना है, उन कारणों से संतुष्ट है कि इन नियमों में प्रदान किए गए तरीके से जांच करना उचित रूप से संभव नहीं है, या,

(iii) जहां राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट है कि राज्य की सुरक्षा के हित में, इन नियमों में प्रदान किए गए तरीके से कोई जांच करना उचित नहीं है, अनुशासनात्मक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकता है और उस पर ऐसे आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे;

बशर्ते कि आयोग से परामर्श किया जाएगा, जहां ऐसे परामर्श आवश्यक हैं, इस नियम के तहत किसी भी मामले में कोई आदेश दिए जाने से पहले।"

"आयोग" शब्द को नियम 2 के खंड (घ) द्वारा "संघ लोक सेवा आयोग" के रूप में परिभाषित किया गया है।

121. C/S नियमों का नियम 37 इस प्रकार है:

"37. कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया- नियम 34, नियम 35 या नियम 36 में निहित किसी भी बात के बावजूद, जहां बल के किसी सदस्य पर एक दंड लगाया जाता है-

(क) ऐसे आचरण के आधार पर जिसके कारण उसे किसी आपराधिक आरोप पर दोषी ठहराया गया है; या

(ख) जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट है, कि उक्त नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना उचित रूप से संभव नहीं है:

अनुशासनात्मक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकता है और उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

बल का एक सदस्य जिसे किसी आपराधिक आरोप पर कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में, आरोप को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है। केवल आरोपित पक्ष को बर्खास्तगी के दंड का प्रस्ताव करते हुए और उससे यह पूछने के लिए एक नोटिस दिया जाएगा कि कठोर कारावास की सजा पाने के कारण उस पर बर्खास्तगी का प्रस्तावित दंड क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। नियम 42 नियम 31 में निर्दिष्ट किसी भी दंड को लगाने वाले आदेश के मामले में अपील का अधिकार प्रदान करता है। नियम 42-ए

अपील दायर करने की अवधि निर्धारित करता है। हालांकि, अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर करने में देरी को माफ करने की शक्ति है यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि अपीलकर्ता के पास समय पर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था। नियम 47 का उप-नियम (2) इस प्रकार प्रदान करता है:

"47. अपीलों पर विचार -

(2) नियम 31 में निर्दिष्ट किसी भी दंड को लगाने वाले आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में, अपीलीय प्राधिकारी निम्नलिखित पर विचार करेगा:

(क) क्या इन नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है, और यदि नहीं, तो क्या ऐसे गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है या न्याय में विफलता हुई है;

(ख) क्या निष्कर्ष उचित हैं; और

(ग) क्या लगाया गया दंड अत्यधिक, पर्याप्त या अपर्याप्त है; और आदेश पारित करेगा;

(i) दंड को रद्द करना, कम करना, पुष्टि करना या बढ़ाना;

(ii) मामले को उस प्राधिकारी को वापस भेजना जिसने दंड लगाया था; या किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसे निर्देश के साथ भेजना जिसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।

नियम 49 स्वतः संज्ञान संशोधन (*suo motu revision*) का प्रावधान करता है। यह अन्य बातों के साथ-साथ, संशोधित करने वाले प्राधिकारी को और सबूत लेने में सक्षम बनाता है और यह प्रावधान करता है कि अपील

से संबंधित नियम 47 के प्रावधान, जहाँ तक संभव हो, संशोधन में दिए गए आदेशों पर लागू होंगे।

130. खंड (ख) के आवेदन के लिए पूर्व शर्त यह है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी को यह संतुष्टि होनी चाहिए कि अनुच्छेद 311 के खंड (2) द्वारा परिकल्पित जांच करना "उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है" (*not reasonably practicable to hold*)। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि उपयोग किए गए शब्द "उचित रूप से व्यावहारिक नहीं" हैं, न कि केवल "अव्यावहारिक" (*impracticable*)। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, "व्यावहारिक" (*practicable*) का अर्थ है, "अभ्यास में लाया जा सकने वाला, क्रिया में निष्पादित, प्रभावी, संपन्न या किया जा सकने वाला; संभव (*feasible*)"। वेबस्टर की थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी "व्यावहारिक" शब्द को अन्य बातों के साथ-साथ "अभ्यास या निष्पादन में संभव: जिसे अभ्यास में लाया जा सके, किया जा सके या संपन्न किया जा सके: संभव" के रूप में परिभाषित करती है। इसके अलावा, उपयोग किए गए शब्द "व्यावहारिक नहीं" नहीं हैं, बल्कि "उचित रूप से व्यावहारिक नहीं" हैं। वेबस्टर की थर्ड न्यू इंटरनेशनल शब्द "उचित रूप से" (*reasonably*) को "उचित तरीके से: काफी हद तक पर्याप्त" के रूप में परिभाषित करती है। इस प्रकार, क्या जांच करना व्यावहारिक था या नहीं, इसका निर्णय इस संदर्भ में किया जाना चाहिए कि क्या ऐसा करना उचित रूप से व्यावहारिक था। खंड (ख) के लिए कुल या पूर्ण अव्यावहारिकता की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक यह है कि एक उचित व्यक्ति के विचार में, मौजूदा स्थिति का उचित दृष्टिकोण लेते हुए, जांच करना व्यावहारिक नहीं है। उन मामलों की गिनती करना संभव नहीं है जिनमें जांच करना उचित

रूप से व्यावहारिक नहीं होगा, लेकिन कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। किसी सरकारी कर्मचारी, विशेष रूप से उसके सहयोगियों के माध्यम से या उनके साथ, गवाहों को जो उसके खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं, प्रतिशोध के डर से इतना आतंकित, धमकी या डरा दिया जाए कि वे ऐसा करने से रुक जाएं, या जहाँ सरकारी कर्मचारी खुद या दूसरों के साथ या उनके माध्यम से उस अधिकारी को धमकाता, डराता और आतंकित करता है जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी है या उसके परिवार के सदस्य को, ताकि वह जांच करने या उसे आयोजित करने का निर्देश देने से डरता हो, तो ऐसी स्थिति में जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं होगा। इसके अलावा, जहाँ हिंसा या सामान्य अनुशासनहीनता और अवज्ञा का माहौल व्याप्त हो, वहाँ भी जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं होगा, और यह मायने नहीं रखता कि संबंधित सरकारी कर्मचारी ऐसे माहौल को बनाने में भागीदार है या नहीं। इस संबंध में, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि संख्याएँ (numbers) आतंकित और डराती हैं जबकि एक व्यक्ति (individual) ऐसा नहीं कर सकता। जांच करने की उचित व्यावहारिकता अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा किया जाने वाला एक आकलन का विषय है। ऐसा प्राधिकारी आम तौर पर घटनास्थल पर होता है और जानता है कि क्या हो रहा है। चूंकि अनुशासनात्मक प्राधिकारी इसका सबसे अच्छा निर्णायक होता है, इसलिए अनुच्छेद 311 का खंड (3) इस प्रश्न पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निर्णय को अंतिम बनाता है। एक अनुशासनात्मक प्राधिकारी से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वह किसी अनुशासनात्मक जांच को हल्के ढंग से या मनमाने ढंग से या गलत उद्देश्यों से या केवल जांच से बचने के लिए या इसलिए समाप्त कर दे कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभाग का मामला कमजोर है और असफल हो

जाएगा। अनुच्छेद 311(3) द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निर्णय को दी गई अंतिमता न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति के संबंध में न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं है और ऐसे मामले में न्यायालय जांच को समाप्त करने वाले आदेश के साथ-साथ दंड लगाने वाले आदेश को भी रद्द कर देगा। अर्जुन चौबे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, [1984] 3 S.C.R. 302 का मामला इसका एक उदाहरण है। उस मामले में, अपीलकर्ता उत्तरी रेलवे, वाराणसी के मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक के कार्यालय में एक वरिष्ठ क्लर्क के रूप में कार्यरत था। वरिष्ठ वाणिज्यिक अधिकारी ने अपीलकर्ता को एक पत्र लिखकर उप मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक से संबंधित घोर अनुशासनहीनता के बारह आरोपों के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा। अपीलकर्ता ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया और ठीक अगले ही दिन उप मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक ने अपीलकर्ता को दूसरा नोटिस दिया, जिसमें कहा गया कि उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है और उसे उन आरोपों के संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने का एक और मौका दिया जा रहा है। अपीलकर्ता ने अपना और स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, लेकिन ठीक अगले ही दिन उप मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक ने उसे इस आधार पर सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया कि वह सेवा में रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। इस न्यायालय ने आदेश को रद्द कर दिया और यह माना कि बारह में से सात आरोप अपीलकर्ता के आचरण से उप मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक, जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी था, से संबंधित थे और यदि जांच की जाती, तो विभाग का मुख्य गवाह स्वयं उप मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक होता, जिसके परिणामस्वरूप वही व्यक्ति मुख्य आरोपी, मुख्य गवाह और मामले का न्यायाधीश होता।

134. यह स्पष्ट है कि जांच को समाप्त करने का कारण लिखित में दर्ज करना दंड लगाने वाले आदेश से पहले होना चाहिए। इसलिए, जांच को समाप्त करने का कारण अंतिम आदेश में होना आवश्यक नहीं है। यह सामान्य होगा कि कारण को अलग से दर्ज किया जाए और फिर लगाए जाने वाले दंड के प्रश्न पर विचार किया जाए और दंड लगाने का आदेश पारित किया जाए। हालांकि, अंतिम आदेश में कारण दर्ज करना बेहतर होगा ताकि इस आरोप से बचा जा सके कि कारण अंतिम आदेश पारित होने से पहले लिखित में दर्ज नहीं किया गया था बल्कि बाद में मनगढ़ंत था। जांच को समाप्त करने के कारण में विस्तृत विवरण होना आवश्यक नहीं है, लेकिन कारण अस्पष्ट या केवल दूसरे प्रावधान के खंड (ख) की भाषा की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा केवल यह कहना कि वह संतुष्ट था कि कोई भी जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं था, खंड (ख) की आवश्यकता का अनुपालन नहीं होगा। कभी-कभी ऐसी स्थिति हो सकती है कि जांच को समाप्त करने के लिए विस्तृत कारण देना उचित रूप से व्यावहारिक न हो। हालांकि, यह स्वतः ही आदेश को अमान्य नहीं करेगा। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने गुणों और उसके अपने तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में किया जाना चाहिए।

140. अब हम अनुच्छेद 311(2) के दूसरे प्रावधान के अंतिम खंड, अर्थात्, खंड (ग) की ओर मुड़ते हैं। हालांकि अनुच्छेद 311(2) में दिए गए सुरक्षा उपायों पर इसका बहिष्करण संचालन अन्य दो खंडों के समान है, यह सामग्री में उनसे बहुत अलग है। जबकि खंड (ख) के तहत संतुष्टि अनुशासनात्मक प्राधिकारी की होनी चाहिए, खंड (ग) के तहत यह राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल की, जैसा भी मामला हो, होनी चाहिए। इसके

अलावा, जबकि खंड (ख) के तहत संतुष्टि इस संबंध में होनी चाहिए कि क्या जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है, खंड (ग) के तहत यह इस संबंध में होनी चाहिए कि क्या राज्य की सुरक्षा के हित में जांच करना उचित नहीं होगा। इस प्रकार, एक मामले में, परीक्षण जांच करने की उचित व्यावहारिकता का है, दूसरे मामले में, यह जांच करने की उपयुक्तता का है। जबकि खंड (ख) स्पष्ट रूप से यह मांग करता है कि जांच को समाप्त करने का कारण लिखित में दर्ज किया जाना चाहिए, खंड (ग) ऐसा नहीं करता है, न तो स्पष्ट रूप से और न ही निहित रूप से।

141. "कानून और व्यवस्था", "सार्वजनिक व्यवस्था" और "राज्य की सुरक्षा" वाक्यांशों का उपयोग विभिन्न अधिनियमों में किया गया है। "सार्वजनिक व्यवस्था" को प्रभावित करने वाली स्थितियाँ उन स्थितियों से अधिक गंभीर होती हैं जो "कानून और व्यवस्था" को प्रभावित करती हैं और "राज्य की सुरक्षा" को प्रभावित करने वाली स्थितियाँ उन स्थितियों से अधिक गंभीर होती हैं जो "सार्वजनिक व्यवस्था" को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार, इन स्थितियों में से "राज्य की सुरक्षा" को प्रभावित करने वाली स्थितियाँ सबसे गंभीर होती हैं। राज्य की सुरक्षा को खतरा राज्य के बाहर या भीतर से उत्पन्न हो सकता है। "राज्य की सुरक्षा" वाक्यांश का अर्थ पूरे देश या पूरे राज्य की सुरक्षा नहीं है। इसमें राज्य के एक हिस्से की सुरक्षा शामिल है। इसे सशस्त्र विद्रोह या बगावत तक भी सीमित नहीं किया जा सकता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे राज्य की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। यह राज्य के रहस्यों या रक्षा उत्पादन या इसी तरह के मामलों से संबंधित जानकारी को अन्य देशों तक पहुँचाने से प्रभावित हो सकती है, चाहे वे हमारे देश के शत्रु हों या नहीं, या आतंकवादियों के साथ गुप्त संबंधों से। उन

विभिन्न तरीकों की गिनती करना मुश्किल है जिनसे राज्य की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। जिस तरीके से राज्य की सुरक्षा प्रभावित होती है, वह या तो खुला या गुप्त हो सकता है। सबसे स्पष्ट कृत्यों में से जो राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, वे सशस्त्र बलों या अर्धसैनिक बलों में असंतोष होगा। इन बलों में असंतोष फैलने की संभावना है, क्योंकि असंतुष्ट या असंतुष्ट सदस्य ऐसे असंतोष और असंतोष को बल के अन्य सदस्यों के बीच फैलाते हैं और इस प्रकार उन्हें अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन न करने और अनुशासनहीनता, अवज्ञा और अपने वरिष्ठों के आदेशों की अवज्ञा के कृत्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसी स्थिति केवल कानून और व्यवस्था या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला मामला नहीं हो सकती है, बल्कि यह राज्य की सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने वाला मामला है। इस संबंध में, पुलिस बल सैन्य या अर्धसैनिक बल के समान ही है क्योंकि इसे कानून और व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने और बनाए रखने का कर्तव्य सौंपा गया है, और पुलिस बल के सदस्यों द्वारा अनुशासन का उल्लंघन और अवज्ञा और अवज्ञा के कृत्यों को सैन्य या अर्धसैनिक बलों के सदस्यों द्वारा इसी तरह के कृत्यों से कम गंभीरता से नहीं देखा जा सकता है। इन बलों के सदस्यों द्वारा अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन और उनके बीच अनुशासन का रखरखाव कितना महत्वपूर्ण माना जाता है, यह संविधान के अनुच्छेद 33 से देखा जा सकता है। संविधान (पचासवाँ संशोधन) अधिनियम, 1984 से पहले, अनुच्छेद 33 इस प्रकार प्रदान करता था:

"33. संसद को इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों पर उनके आवेदन में संशोधित करने की शक्ति। संसद कानून द्वारा यह निर्धारित कर सकती है

कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई भी सशस्त्र बलों के सदस्यों या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव का आरोप रखने वाले बलों पर उनके आवेदन में किस हद तक प्रतिबंधित या समाप्त किया जाएगा ताकि उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन और उनके बीच अनुशासन का रखरखाव सुनिश्चित हो सके।"

संविधान (पचासवाँ संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा, इस अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया गया था। प्रतिस्थापित अनुच्छेद द्वारा संसद की किसी भी मौलिक अधिकार के आवेदन को प्रतिबंधित या समाप्त करने की शक्ति का दायरा व्यापक बनाया गया है। प्रतिस्थापित अनुच्छेद 33 इस प्रकार है:

"33. संसद को इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों, आदि पर उनके आवेदन में संशोधित करने की शक्ति। संसद, कानून द्वारा, यह निर्धारित कर सकती है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई भी,

(क) सशस्त्र बलों के सदस्यों; या

(ख) सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव का आरोप रखने वाले बलों के सदस्यों; या

(ग) राज्य द्वारा खुफिया या प्रति-खुफिया उद्देश्यों के लिए स्थापित किसी भी ब्यूरो या अन्य संगठन में कार्यरत व्यक्तियों; या

(घ) खंड (क) से (ग) में संदर्भित किसी भी बल, ब्यूरो या संगठन के उद्देश्यों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणालियों में या उनके संबंध में कार्यरत व्यक्तियों पर उनके आवेदन में किस हद तक प्रतिबंधित या समाप्त किया

जाएगा ताकि उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन और उनके बीच अनुशासन का रखरखाव सुनिश्चित हो सके।"

इस प्रकार, इन बलों के सदस्यों द्वारा उनके कर्तव्यों का निर्वहन और उनके बीच अनुशासन का रखरखाव देश के लिए इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि इसे सुनिश्चित करने के लिए संविधान ने संसद को उन पर उनके आवेदन में किसी भी मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित या समाप्त करने की शक्ति प्रदान की है।

147. हमारे समक्ष सभी मामलों में, चुनौती केवल कानूनी आधारों तक ही सीमित थी, जिसमें मुख्य आधार चलप्पन के मामले में क्या माना गया था और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आवेदन पर आधारित था। इन आधारों के संबंध में तर्कों पर हमने इस निर्णय के पिछले भाग में विचार किया है और उन्हें नकार दिया है। अधिकांश मामलों में, रिट याचिकाओं में कोई विस्तृत तथ्य नहीं है। कई याचिकाकर्ताओं ने विभागीय अपील में भाग लिया है, लेकिन उस तथ्य का रिट याचिकाओं में उल्लेख नहीं किया गया है और न ही अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को चुनौती दी गई है जहाँ अपीलें खारिज कर दी गई हैं। कई सरकारी कर्मचारियों ने एक साथ मिलकर एक रिट याचिका दायर की है और उनमें से जिन लोगों की विभागीय अपीलों को स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें सेवा में बहाल कर दिया गया है, उन मामलों में याचिकाओं में उनके नाम हटाने के लिए संशोधन नहीं किया गया है और वे याचिकाकर्ताओं के रूप में रिकॉर्ड पर बने रहे हैं। कई याचिकाएँ एक जैसी शर्तों में हैं, यदि बिल्कुल सटीक प्रतियाँ नहीं तो अन्य याचिकाओं की हैं। ऐसे मामलों में एक याचिकाकर्ता के मामले को दूसरे से अलग करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। *impugned*

आदेशों की कानूनी वैधता का विरोध करने के अलावा, शायद ही किसी ने अपनी याचिका में यह कहा हो कि वह उस स्थिति में शामिल नहीं था जिसके कारण अनुच्छेद 311 के दूसरे प्रावधान के खंड (ख) या खंड (ग) को उसके मामले में लागू किया गया था। *impugned* आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी के खिलाफ कदाचार का कोई आरोप नहीं है सिवाय कभी-कभी एक मात्र आरोप के कि आदेश कदाचार से पारित किया गया था। ऐसे कथित कदाचार का कोई भी विवरण नहीं दिया गया है। ऐसा मात्र कथन कदाचार की दलील नहीं हो सकता है और इसे अनदेखा करने की आवश्यकता है। तथ्यों के संबंध में इस असंतोषजनक स्थिति में, एकमात्र तरीका जो यह न्यायालय अपना सकता है वह यह है कि क्या अनुच्छेद 311(2) के दूसरे प्रावधान का प्रासंगिक खंड या एक समान सेवा नियम को ठीक से लागू किया गया है या नहीं। यदि यह न्यायालय पाता है कि ऐसे प्रावधान को ठीक से लागू नहीं किया गया है, तो अपीलकर्ता या याचिकाकर्ता, जैसा भी मामला हो, सफल होने का हकदार है। हालाँकि, यदि हम पाते हैं कि इसे ठीक से लागू किया गया है, तो अपील या याचिका को खारिज किया जाना होगा, क्योंकि न्यायालय के समक्ष यह जांच करने और यह पता लगाने के लिए कोई उचित सामग्री नहीं है कि क्या कोई विशेष सरकारी कर्मचारी, वास्तव में, उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों का दोषी था या नहीं। ऐसा करना इस न्यायालय का कार्य भी नहीं है क्योंकि इसमें तथ्यों के विवादित प्रश्नों की जांच शामिल होगी और यह न्यायालय, एक दुर्लभ मामले को छोड़कर, ऐसी जांच शुरू नहीं करेगा। इन कारणों से और इन मामलों का निपटान करते समय हम जो निर्देश देने का प्रस्ताव करते हैं, उसके मद्देनजर, हम तथ्यों से निपटते समय किसी भी पहलू को छूने से

बचेंगे सिवाय इसके कि क्या अनुच्छेद 311(2) के दूसरे प्रावधान का विशेष खंड या एक समान सेवा नियम ठीक से लागू किया गया था या नहीं।"

14. इस न्यायालय ने रमेश चंद्र बनाम द टोंक जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, टोंक और अन्य, रिपोर्टेड in 2004 WLC (Raj.) UC 733 में, तुलसाराम पटेल (supra) के मामले में निर्धारित कानून पर विचार करने के बाद, पैरा 12, 13 और 14 में निम्नलिखित अवलोकन किए हैं:

"12. नियम 19 के प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इन असाधारण शक्तियों का उपयोग विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है जब 1958 के नियमों के नियम 16 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी बैंक ने यह मानते हुए नियम 19 के खंड 2 का सहारा लिया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं था। इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी बैंक 1958 के नियमों के नियम 16 के तहत प्रदान की गई जांच की नियमित प्रक्रिया को समाप्त करके 1958 के नियमों के नियम 19 के खंड 2 के तहत शक्तियों का सहारा लेने में सही था। जैसा कि पिछले पैराग्राफ में कहा गया है, याचिकाकर्ता ने 1958 के नियमों के नियम 16 के तहत जापन प्राप्त करने के तुरंत बाद, प्रतिवादी बैंक को एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उसे कुछ जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया गया जो प्रभावी बचाव बयान प्रस्तुत करने के लिए

आवश्यक थी, जो याचिकाकर्ता की राय में प्रभावी बचाव बयान प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक थे। याचिकाकर्ता ने उस आवेदन में भी काफी स्पष्ट शब्दों में उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया। यह प्रतिवादियों के लिए उस स्तर पर भी याचिकाकर्ता के खिलाफ नियमित जांच के साथ आगे बढ़ना खुला था। प्रतिवादी बैंक ने ऐसा करने के बजाय 1958 के नियमों के नियम 19(2) के तहत शक्तियों का सहारा लेना चुना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम तुलसाराम पटेल रिपोर्टेड in 1985 SC page 1416 के मामले में, इस संबंध में दिशानिर्देश दिए हैं। मैं ऊपर संदर्भित निर्णय के प्रासंगिक हिस्से को पुनः प्रस्तुत करना चाहूंगा जो उन परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है जिनमें नियमित कार्यवाही को समाप्त करने के लिए विशेष शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है:

"(पैरा 130) खंड (ख) के आवेदन के लिए पूर्व शर्त अनुशासनात्मक प्राधिकारी की यह संतुष्टि है कि अनुच्छेद 311 के खंड (2) द्वारा परिकल्पित जांच करना "उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है" (*not reasonably practicable to hold*)। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि उपयोग किए गए शब्द "उचित रूप से व्यावहारिक नहीं" हैं, न कि केवल "अव्यावहारिक"। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, "व्यावहारिक" (*practicable*) का अर्थ है, "अभ्यास में लाया जा सकने वाला, क्रिया में निष्पादित, प्रभावी, संपन्न या किया जा सकने वाला; संभव (*feasible*)"। वेबस्टर की थर्ड न्यू

इंटरनेशनल डिक्शनरी "व्यावहारिक" शब्द को अन्य बातों के साथ-साथ "अभ्यास या निष्पादन में संभव: किया जा सके या संपन्न किया जा सके: संभव" के रूप में परिभाषित करती है। इसके अलावा, उपयोग किए गए शब्द "व्यावहारिक नहीं" नहीं हैं, बल्कि "उचित रूप से व्यावहारिक नहीं" हैं। वेबस्टर की थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी शब्द "उचित रूप से" (*reasonably*) को "उचित तरीके से: काफी हद तक पर्याप्त" के रूप में परिभाषित करती है। इस प्रकार, क्या जांच करना व्यावहारिक था या नहीं, इसका निर्णय इस संदर्भ में किया जाना चाहिए कि क्या ऐसा करना उचित रूप से व्यावहारिक था। खंड (ख) के लिए कुल या पूर्ण अव्यावहारिकता की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक यह है कि एक उचित व्यक्ति के विचार में, मौजूदा स्थिति का उचित दृष्टिकोण लेते हुए, जांच करना व्यावहारिक नहीं है। उन मामलों की गिनती करना संभव नहीं है जिनमें जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं होगा, लेकिन कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। किसी सरकारी कर्मचारी, विशेष रूप से उसके सहयोगियों के माध्यम से या उनके साथ, गवाहों को जो उसके खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं, प्रतिशोध के डर से इतना आतंकित, धमकी या डरा दिया जाए कि वे ऐसा करने से रुक जाएं, या जहाँ सरकारी कर्मचारी खुद या दूसरों के साथ या उनके माध्यम से उस अधिकारी को धमकाता, डराता और आतंकित करता है जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी है या उसके परिवार के सदस्य को, ताकि वह जांच करने या उसे आयोजित करने का निर्देश देने से डरता हो, तो ऐसी स्थिति में जांच

करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं होगा, यह भी उचित रूप से व्यावहारिक नहीं होगा जहाँ हिंसा या सामान्य अनुशासनहीनता और अवज्ञा का माहौल व्याप्त हो, और यह मायने नहीं रखता कि संबंधित सरकारी कर्मचारी ऐसे माहौल को बनाने में भागीदार है या नहीं। इस संबंध में, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि संख्याएँ (*numbers*) आतंकित और डराती हैं जबकि एक व्यक्ति (*individual*) ऐसा नहीं कर सकता। जांच करने की उचित व्यावहारिकता अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा किया जाने वाला एक आकलन का विषय है। ऐसा प्राधिकारी आम तौर पर घटनास्थल पर होता है और जानता है कि क्या हो रहा है। चूंकि अनुशासनात्मक प्राधिकारी इसका सबसे अच्छा निर्णायक होता है, इसलिए अनुच्छेद 311 का खंड (3) इस प्रश्न पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निर्णय को अंतिम बनाता है। एक अनुशासनात्मक प्राधिकारी से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वह किसी अनुशासनात्मक जांच को हल्के ढंग से या मनमाने ढंग से या गलत उद्देश्यों से या केवल जांच से बचने के लिए या इसलिए समाप्त कर दे कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभाग का मामला कमजोर है और असफल हो जाएगा। अनुच्छेद 311(3) द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निर्णय को दी गई अंतिमता न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति के संबंध में न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं है और ऐसे मामले में न्यायालय जांच को समाप्त करने वाले आदेश के साथ-साथ दंड लगाने वाले आदेश को भी रद्द कर देगा। "

13. वर्तमान मामले के तथ्यों के सूक्ष्म विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादियों के पास 1958 के नियमों के नियम 16 के तहत प्रदान की गई नियमित जांच को समाप्त करने और 1958 के नियमों के नियम 19(1) के तहत शक्तियों का उपयोग करने के लिए कोई भी परिस्थिति उपलब्ध नहीं थी।
14. अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने 1958 के नियमों के नियम 19(ii) के तहत शक्तियों का सहारा केवल 1958 के नियमों के नियम 16 के तहत निर्धारित अनुशासनात्मक जांच को टालने के लिए लिया। याचिकाकर्ता को किसी भी तरह से जांच में बाधा डालने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। प्रतिवादियों द्वारा लिया गया आधार बिना किसी कारण के प्रतीत होता है। इसे देखते हुए, *impugned* आदेश Annex.6 को रद्द और निरस्त करने योग्य है।"
15. ऊपर की गई चर्चा और ऊपर संदर्भित और स्थापित कानून के मद्देनजर, यह न्यायालय सुरक्षित रूप से यह मान सकता है कि वर्तमान मामले में 1958 के नियमों के नियम 19(ii) के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग पूरी तरह से अवैध, मनमाना और असंवैधानिक है, क्योंकि सबसे पहले, वर्तमान मामले के तथ्य ऐसे नहीं हैं कि नियमित जांच को समाप्त किया जा सके, दूसरे, याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों को केवल जांच के बाद ही साबित किया जा सकता है और तीसरे, नियमित जांच को समाप्त करने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी की संतुष्टि का कारण बनी सामग्री और कारणों का न तो अंतिम आदेश में खुलासा किया गया है और न ही इस न्यायालय के समक्ष इसका खुलासा किया गया है। याचिकाकर्ता को

सेवा से बर्खास्त करने का impugned आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का घोर उल्लंघन है।

16. प्रतिवादियों ने यह भी आपत्ति उठाई है कि 08.04.2022 के आदेश के खिलाफ रिट याचिका, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता पर सेवा से बर्खास्तगी का दंड लगाया गया है, सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता के पास 1958 के नियमों के तहत प्रदान किए गए अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील का एक वैधानिक उपाय है।

17. यह एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है जब याचिकाकर्ता के पास किसी भी कानून के तहत एक वैकल्पिक वैधानिक उपाय है सिवाय चार असाधारण परिस्थितियों के। चार असाधारण परिस्थितियों में से एक यह है कि रिट याचिका को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सीधे सुनवाई योग्य माना जा सकता है जब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का घोर उल्लंघन होता है।

व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स, मुंबई और अन्य, रिपोर्टेड in 1998 (8) SCC 1 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन अपवादों को बताया जहाँ एक रिट न्यायालय किसी पार्टी द्वारा statute द्वारा प्रदान किए गए वैकल्पिक उपाय का लाभ न उठाने के बावजूद एक रिट याचिका को स्वीकार करने में उचित होगा। वे निम्नलिखित हैं:

"(i) जहाँ रिट याचिका किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन की मांग करती है; या

(ii) जहाँ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होता है; या

(iii) जहाँ आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से क्षेत्राधिकार के बिना हैं; या

(iv) जहाँ अधिनियम के विरेस को चुनौती दी जाती है।"

असिस्टेंट कमिशनर ऑफ स्टेट टैक्स और अन्य बनाम कमर्शियल स्टील लिमिटेड, रिपोर्टेड in 2021 SCC Online SC 884 के मामले में उन्हीं सिद्धांतों को दोहराया गया।

18. चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऊपर संदर्भित मामलों में और विभिन्न अन्य मामलों में यह माना है कि यदि आदेश या कार्यवाही को चुनौती दी जाती है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का घोर उल्लंघन है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट को सीधे स्वीकार किया जा सकता है, भले ही statute के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपाय का उपयोग न किया गया हो।

19. यह न्यायालय पहले ही मान चुका है कि पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा पारित 08.04.2022 का आदेश, जिसमें सेवा से बर्खास्तगी का दंड लगाया गया था, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का घोर उल्लंघन है, और इसलिए प्रतिवादियों के वकील द्वारा उठाई गई आपत्ति कि रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, उसे खारिज कर दिया जाता है।

20. तदनुसार, रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा पारित 08.04.2022 का आदेश, जिसमें याचिकाकर्ता

को सेवा से बर्खास्त किया गया था, को सभी परिणामी लाभों सहित वेतन, वेतन निर्धारण और अन्य सेवा लाभों आदि के साथ रद्द किया जाता है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को सेवा में शामिल होने दें और आज से तीन महीने के भीतर याचिकाकर्ता को परिणामी लाभ प्रदान करें।

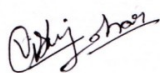
हालांकि, प्रतिवादियों को 1958 के नियमों के तहत उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में नियमित जांच कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता होगी।

21. मुख्य याचिका में पारित आदेश को देखते हुए, स्थगन आवेदन और लंबित आवेदन, यदि कोई हो, भी निपटाए जाते हैं।

(गणेश राम मीणा), जे

शर्मा एनके/डिप्टी रजिस्ट्रार

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़